

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

❖ सन्दर्भ

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि 2014-2015 में भारत में एफडीआई प्रवाह 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा 2014-2015 से भारत के एफडीआई में निरंतर वृद्धि हुई है, और भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अनंतिम आंकड़े) के साथ अपना उच्चतम वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया है।

प्रमुख बिंदु :-

सरकार द्वारा किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में वृद्धि हुई है।

● शीर्ष पांच एफडीआई स्रोत राष्ट्र

- सिंगापुर (27.01%), यूएसए (17.94%), मॉरीशस (15.98%), नीदरलैंड (7.86%) और स्विट्जरलैंड (7.31%) वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह के लिए शीर्ष 5 देशों के रूप में उभरे हैं।

● वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी

प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र हैं

- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (24.60%), सेवा क्षेत्र (12.13%), ऑटोमोबाइल उद्योग (11.89%), व्यापार (7.72%) और निर्माण (बुनियादी ढांचा) गतिविधियाँ (5.52%)।

● वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी

अंतर्प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं

- कर्नाटक (37.55%), महाराष्ट्र (26.26%), दिल्ली (13.93%), तमिलनाडु (5.10%) और हरियाणा (4.76%)

● UNCTAD विश्व निवेश रिपोर्ट (WIR) 2022 के अनुसार, FDI प्रवाह में वैश्विक रुझानों के अपने विश्लेषण में, भारत ने 2021 के लिए शीर्ष 20 एफडीआई प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्थाओं में एक स्थान सुधार कर 7वें स्थान पर आ गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

● के बारे में

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तब होता है जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश के किसी व्यवसाय इकाई में नियंत्रण स्वामित्व लेती है।
- एफडीआई के साथ, विदेशी कंपनियाँ सीधे दूसरे देश में कार्यप्रबंधन में सम्मिलित होती हैं।
- इसका मतलब है कि वे न केवल अपने साथ पैसा ला रहे हैं, बल्कि ज्ञान, कौशल और तकनीक भी ला रहे हैं।

● भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने के मार्ग :-

स्वचालित रूटिंग :-

- अनिवासी या भारतीय कंपनी को एफडीआई के लिए आरबीआई या भारत सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

सरकारी मार्ग

इस मार्ग से एफडीआई प्राप्त करने के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य है।

- कंपनी को एक आवेदन दाखिल करना होगा।
- इसके बाद आवेदन संबंधित मंत्रालय को भेजा जाता है, जो आवेदन को स्वीकृत/अथवा अस्वीकृत करेगा।
- वर्तमान एफडीआई नीति के तहत आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए डीपीआईआईटी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा।

○ उद्योग : जहां एफडीआई सख्त वर्जित है

- परमाणु ऊर्जा उत्पादन, कोई जुआ या सट्टेबाजी का कारोबार लॉटरी (ऑनलाइन, निजी, सरकारी, आदि), चिट फंड निधि कंपनी में निवेश, कृषि या वृक्षारोपण गतिविधियाँ, सिगार, सिगरेट।

लीगेसी लैंडफिल साइट्स

❖ सन्दर्भ

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एसबीएम-यू डैशबोर्ड के अनुसार, पांच राज्यों में 1,080 "लीगेसी लैंडफिल साइट्स" में से आधे से अधिक के लिए प्राधिकारियों ने अभी तक सुधारात्मक प्रस्ताव नहीं दिए हैं।

प्रमुख बिंदु :-

● डैशबोर्ड ने बताया कि देश भर में 18.67 करोड़ टन कचरे के साथ लगभग 47,456.66 एकड़ में विस्तारित 1,854 लैंडफिल साइट्स में अभी सुधार होना बाकि है।

● डंप साइटों को साफ करने के बाद, नगर पालिकाओं को भूमि के वैकल्पिक उपयोग के लिए योजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता होती है।

Face to Face Centres



● सुधार योग्य 1,080 साइट्स में से 591 साइट्स मात्र पांच राज्यों में हैं - ये क्रमशः कर्नाटक (136), राजस्थान (128), आंध्र प्रदेश (115), मध्य प्रदेश (111), और तेलंगाना (101) में स्थित हैं।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0

- यह मिशन पिछले साल लॉन्च किया गया था।
- इसमें "कचरा मुक्त शहर" बनाने और 2026 (मिशन के 5 वर्ष के उपरांत) के अंत तक सभी लैंडफिल साइट्स का 100% उपचार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- मिशन के अंतर्गत, नगर पालिकाओं को लीगेसी लैंडफिल के बायोरेमेडिएशन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- संरचना के आधार पर, कचरे को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है
 - अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों के लिए अस्वीकृत व्युत्पन्न ईंधन (RDF)।
 - सी एंड डी संयंत्रों द्वारा पुनर्चक्रण के लिए निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट।
 - जैव-मृदा -जिसका उपयोग सड़क निर्माण में अंतराल को भरने के लिए किया जा सकता है।

जैव उपचार

- बायोरेमेडिएशन, जैव प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जो मिट्टी, पानी और अन्य वातावरण से दूषित पदार्थों, प्रदूषकों और विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए सूक्ष्मजीवों और जीवाणुओं जैसे जीवित जीवों का उपयोग करती है।
- यह स्वस्थाने (इन सीटू - संदूषण स्थल पर) तथा परस्थाने ("एक्स सीटू साइट से दूर अन्य स्थान पर) दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
- यदि जलवायु सूक्ष्म जीव गतिविधि को बनाए रखने के लिए बहुत ठंडी है, या पोषक तत्वों को समान रूप से वितरित करने के लिए मिट्टी बहुत घनी है, तो स्वस्थाने बायोरेमेडिएशन आवश्यक हो जाता है।
- एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन के लिए जमीन के ऊपर की मिट्टी की खुदाई और सफाई की आवश्यकता हो सकती है, जो प्रक्रिया की लागत में वृद्धि कर देती है।

संक्षिप्त सुर्खियां

प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन



❖ प्रसंग

हाल ही में, सरकार ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन (PADMA) को देश भर में समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए एक स्व-नियामक निकाय के रूप में मंजूरी दी है।

❖ मुख्य विशेषताएं

➤ के बारे में

■ यह संगठन - 47 डिजिटल समाचार प्रकाशकों के साथ - अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मीडिया समाचार सामग्री से संबंधित शिकायतों का अवलोकन करेगा।

➤ सदस्य

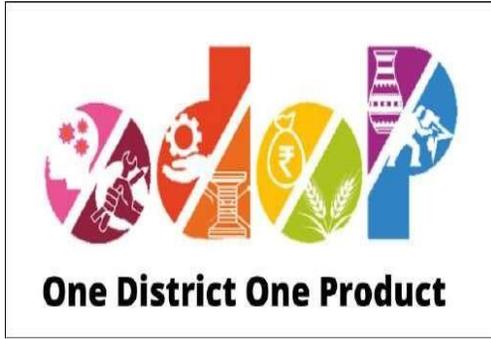
संगठन का नेतृत्व उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मूलचंद गर्ग करेंगे तथा प्रसार भारती के अंशकालिक सदस्य अशोक कुमार टंडन और पत्रकार मनोज कुमार मिश्रा इसके सदस्य होंगे।

- इसके साथ ही मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 12 के तहत मई 2021 से नौ स्व-नियामक निकायों को मंजूरी दे दी है।
- इन निकायों में डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, ऑनलाइन मीडिया परिसंघ (इंडिया) और एनबीएफ-प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी समेत अन्य सम्मिलित हैं।
- स्व-नियामक निकाय के मुख्य कार्यों में "निगरानी करना और प्रकाशक द्वारा आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना ; उन शिकायतों का समाधान करना जिन्हें प्रकाशकों द्वारा 15 दिनों के भीतर हल नहीं किया गया है; प्रकाशकों आदि के निर्णय के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई अपीलों की सुनवाई करना, इत्यादि सम्मिलित होगा।

Face to Face Centres



एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी)



❖ प्रसंग

➤ हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल को 'डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब (DEH)' पहल के साथ विलय कर दिया गया है।

❖ मुख्य बिंदु :-

- ओडीओपी पहल को अप्रैल, 2022 में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) श्रेणी के माध्यम से समग्र विकास में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चिन्हित किया गया है।
- ओडीओपी उत्पादों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे विश्व आर्थिक मंच, मई 2022 में दावोस, जून 2022 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईवाईडी) आदि में प्रदर्शित किया जाता है।
- आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं और उनमें से लगभग 13 को DEH पहल में शामिल किया गया है।

❖ एक जनपद एक उत्पाद योजना (ODOP) के बारे में

- इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और इसकी सफलता के कारण बाद में इसे केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया था।
- इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- इसे 'डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब' पहल के साथ विलय कर दिया गया है।
- इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है।

➤ कार्यान्वयन

इसे डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग द्वारा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ एक प्रमुख हितधारक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

➤ उत्पाद और बाजार

- ओडीओपी उत्पाद खराब होने वाला कृषि उत्पाद, अनाज आधारित उत्पाद या किसी जिले और उनके संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य उत्पाद हो सकता है।
- ओडीओपी उत्पाद नेफेड बाजारों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पूरे भारत के प्रमुख खुदरा स्टोरों पर उपलब्ध होंगे।

➤ उद्देश्य

- जिलों को निर्यात केंद्रों में बदलना।
- उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देना।
- रोजगार पैदा करना।

जियो-लदाख (Geo-Ladakh)

❖ प्रसंग

➤ हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने सूचित किया कि यूटी-लदाख सरकार ने यूटी-लदाख के लिए "स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियोपोर्टल 'जियो-लदाख' विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक इकाई, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान (आईआईआरएस) से संपर्क किया है।





❖ मुख्य बिंदु

» परियोजना को पूरा करने के लिए 1 जनवरी, 2022 को IIRS (ISRO) और UT-लद्दाख प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

➤ परियोजना में सुदूर संवेदन, भू-स्थानिक तकनीकों और इस डेटाबेस की मेजबानी के लिए भू-पोर्टल के विकास का उपयोग करके स्थानिक डेटाबेस निर्माण (जल संसाधन, वनस्पति और ऊर्जा क्षमता) सम्मिलित है।

➤ परियोजना का उद्देश्य यूटी-लद्दाख के अधिकारियों को भू-स्थानिक तकनीकों और अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण देना भी है।

➤ पोर्टल यूटी-लद्दाख के लिए भू-स्थानिक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें स्थानिक दर्शक, कार्बन तटस्थता, भू-स्थानिक उपयोगिता मानचित्रण और भू-पर्यटन को सम्मिलित करता है।

➤ महत्व

- इसका उपयोग टाइम सीरीज स्नो कवर, ताजे पानी की उपलब्धता, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (सौर और पवन) के लिए साइटों पर स्थानिक डेटाबेस बनाने के लिए किया जा सकता है।
- यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आवधिक अंतराल पर परिवर्तन मूल्यांकन के लिए अल्पाइन चरागाहों/चराई भूमि की उपलब्धता दिखा सकता है।

❖ प्रसंग

➤ हाल ही में, केंद्र ने सूचित किया कि भारत में भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (NaviC सिस्टम) का उपयोग बढ़ गया है।

❖ मुख्य विशेषताएं

- एनएवीआईसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड-अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है।
- एनएवीआईसी को मूल रूप से 2006 में 174 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया था।
- इसके 2011 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, परन्तु यह 2018 में परिचालित हुआ।
- एनएवीआईसी में आठ उपग्रह हैं और यह पूरे भारत के भूभाग और इसकी सीमाओं से 1,500 किमी (930 मील) तक कवर करता है।
- वर्तमान में, NavIC का उपयोग सीमित है। इसका उपयोग भारत में सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग, मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने के लिए आपातकालीन चेतावनी अलर्ट प्रदान करने (जहां कोई स्थलीय नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है), और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी को ट्रैक करने और प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- इस प्रक्रिया में अगला कदम इसे स्मार्टफोन में इनबिल्ट करना होगा ; जिस पर भारत जोर दे रहा है।

➤ NaviC बनाम GPS

जीपीएस सम्पूर्ण विश्व के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसके उपग्रह दिन में दो बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जबकि एनएवीआईसी वर्तमान में भारत और आस-पास के क्षेत्रों में उपयोग के लिए है।

➤ साइड नोट

- जीपीएस की तरह, वैश्विक कवरेज वाली तीन और नेविगेशन प्रणालियां हैं - यूरोपीय संघ का

इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (NaviC)



Face to Face Centres



गैलीलियो, रूस के स्वामित्व वाला ग्लोनास और चीन का बीदोअ

- QZSS, जापान द्वारा संचालित, एक अन्य क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है जो जापान पर ध्यान केंद्रित करते हुए एशिया-ओशिनिया क्षेत्र को कवर करती है।

नेविगेटिंग द स्टॉर्म रिपोर्ट



❖ सन्दर्भ :-

- विश्व बैंक ने 'नेविगेटिंग द स्टॉर्म' शीर्षक से भारत विकास रिपोर्ट जारी की है।

❖ मुख्य बिंदु

- विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को 6.9% तक अनुमानित किया है।
- रिपोर्ट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था 6.6 % की दर से आगे बढ़ेगी।
- यह बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति अर्थव्यवस्था के सापेक्ष लचीलेपन का सन्दर्भ देता है।
- अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स ने इसे अच्छी स्थिति में रखा है।
- भारत की अर्थव्यवस्था अन्य उभरते बाजारों की तुलना में वैश्विक स्पिलओवर से अपेक्षाकृत आंशिक रूप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि देश में एक बड़ा घरेलू बाजार है तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह अपेक्षाकृत रूप से कम है।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से मौद्रिक नीति को कड़ा करने के परिणामस्वरूप पहले ही बड़े पोर्टफोलियो बहिर्गमन और भारतीय रुपये का मूल्यहास हुआ है।
- उच्च वैश्विक पण्य कीमतों के कारण चालू खाता घाटा में वृद्धि हुई है।

हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में सुधार और विदेशी मुद्रा भंडार के रिजर्व द्वारा चालू-खाता घाटा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है।

❖ प्रसंग

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर (सीएनएपी) की संभावित शुरुआत के बारे में टिप्पणी मांगने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया।

❖ मुख्य बिंदु

- यह फीचर एक व्यक्ति को कॉलिंग पार्टी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
- इस सन्दर्भ में विचार यह सुनिश्चित करना है कि टेलीफोन ग्राहक एक आने वाली कॉल के बारे में सूचित विकल्प बनाने में सक्षम रहे।
- इसके अतिरिक्त, यह अज्ञात स्पैम कॉलर्स द्वारा उत्पीड़न पर अंकुश लगा सकता है और धोखाधड़ी वाले कॉलों से बचा जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, रोबोकॉल के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।
- रोबोकॉल पूर्व-रिकॉर्डेड वॉयस कॉल के साथ आईटी-सक्षम सिस्टम का उपयोग करके स्वचालित रूप से की जाने वाली कॉल हैं।
- हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इस सन्दर्भ में फीचर कॉल करने वाले के गुमनाम रहने के अधिकार को के संतुलन में चिंता व्यक्त की है क्योंकि गुमनाम रहने का अधिकार निजता के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है।

कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर





प्री-बंकिंग

❖ प्रसंग

➤ Google की अनुषंगी Ara भारत में एक नई गलत सूचना-रोधी परियोजना शुरू कर रही है।

❖ मुख्य बिंदु

- इस पहल में "प्रीबंकिंग" वीडियो का उपयोग किया जाएगा जिसे कंपनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर प्रसारित किया जाएगा।
- वीडियो व्यापक होने से पहले झूठे दावों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- यह दृष्टिकोण कई वर्षों के शोध पर आधारित एक विचार है जिसे इनोक्यूलेशन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।
- थ्योरी सुझाव देती है कि हानिरहित, काल्पनिक उदाहरणों का उपयोग करके लोगों को गलत सूचना के प्रक्रिया के बारे में बताकर, झूठे दावों के प्रति उनके बचाव को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- कई आम झूठे दावों में देखी जाने वाली विशेषताओं में भावनात्मक रूप से आवेशित भाषा, व्यक्तिगत हमले या दो असंबंधित वस्तुओं के बीच झूठी तुलना शामिल हैं।
- शोध के अनुसार, जिन लोगों ने वीडियो देखा वे गलत जानकारी और सटीक जानकारी के बीच अंतर करने में काफी बेहतर थे।

❖ तकनीक के लाभ

- पत्रकारिता द्वारा तथ्य की जांच, गलत सूचना को प्रतिबंधित करती है परन्तु यह काफी समयगहन और श्रम गहन हैं।
- विशिष्ट दावों के बजाय सामान्य रूप से गलत सूचना की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करके, प्री-बंकिंग वीडियो एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के विषयों पर झूठे दावों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं।
- सोशल मीडिया कंपनियों की कंटेंट मॉडरेशन करने में विफल रहने और असंगत होने के लिए आलोचना की सकती है।

[MCQ](#), [Current Affairs](#), [Daily Pre Pare](#)

Face to Face Centres

